@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

'जहां-जहां भी भाजपा-एनडीए की सरकार है, विकास जमीन पर उतरा है'

वर्ष-16, अंक-07 01-15 अप्रैल, 2021 (पाक्षिक) ₹20

'विकास, निरंतर विकास और सबका विकास' के लिए प्रतिबद्ध भाजपा

पश्चिम मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) में एक रोड शो में भाग लेते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

बोरगांव (असम) में आयोजित एक जनसभा में
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा व अन्य नेतागण

खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) में एक रोड शो में जनाभिवादन स्वीकार करते
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

नाज़िरा (असम) में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

लुमडिंग (असम) में एक चुनावी सभा को संबोधित करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 आज असम में विकास और विश्वास की लहर है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 मार्च, 2021 को असम के करीमगंज में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश में विकास की गति को और तेज करने एवं असम को देश का एक...

08 कांग्रेस का मिशन कमीशन भाजपा का मिशन जनसेवा: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष...

11 एनडीए सरकार ने असम के विकास की एक ठोस नींव रखी है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 मार्च, 2021 को असम में तिनसुकिया के चाबुआ में आयोजित विशाल जनसभा को...

13 भाजपा तुष्टिकरण की राजनीति और घुसपैठ की समस्या को ख़त्म करके रहेगी: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने...

27 पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ गए हैं: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 16 मार्च को पश्चिम बंगाल के...

वैचारिकी

राष्ट्रवाद को कोई वाद मिटा नहीं सका / **दीनदयाल उपाध्याय** 20

श्रद्धांजलि

नहीं रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी 22
भाजपा सांसद राम स्वरूप शर्मा का आकस्मिक निधन 22

अन्य

'दीदी बोले खेला होबे, भाजपा बोले विकास होबे' 07
'ममता दीदी, आपका जाना और राज्य में कमल खिलना तय है' 10
'दीदी की पार्टी निर्ममता की पाठशाला है' 12
असम विस चुनाव: भाजपा संकल्प-पत्र 14
पश्चिम बंगाल विस चुनाव: सोनार बांग्ला संकल्प-पत्र 15
तमिलनाडु विस चुनाव: भाजपा संकल्प-पत्र 16
17 राज्यों ने 'वन नेशन, वन राशन' कार्ड प्रणाली को किया लागू 17
जीएसटी क्षतिपूर्ति हेतु जारी हुए 1.10 लाख करोड़ रुपये 18
मोज़ाम्बिक को 3000 एचपी केप गेज लोकोमोटिव का निर्यात 19
'बीज से लेकर बाजार तक किसान की हर दिक्कत को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास' 23
भारत कभी अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूलेगा: नरेन्द्र मोदी 24
तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली 26
सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत के लिए मिलकर काम करेंगे: नरेन्द्र मोदी 28
'आयुर्वेदिक उत्पादों की वैश्विक मांग निरंतर बढ़ रही है' 29
'महामारी और आपदाओं के बावजूद मजबूत भारत' 30

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं, जब चुनाव आता है तो कहती हैं– सरकार दुआरे-दुआरे। यही इनका 'खैला' है! पश्चिम बंगाल दीदी का यह 'खैला' समझ गया है। इसलिए यहां की जनता 2 मई को दीदी को दुआर दिखाएगी।

जगत प्रकाश नड्डा

अंधकार, अशांति, पिछड़ापन चाहिए तो कांग्रेस को वोट दीजिए। विकास, शांति और समृद्धि चाहिए तो भाजपा के कमल के निशान पर आप मोहर लगाइये।

अमित शाह

भाजपा ने असम की भाषा, कला और संस्कृति की रक्षा करके असम के विकास को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। श्रीमंत शंकरदेव की भूमि व असम की सांस्कृतिक राजधानी माजुली की विशाल जनसभा में जनता का जोश व उत्साह साफ दर्शाता है कि असम में फिर एक बार कमल खिलने जा रहा है।

राजनाथ सिंह

पश्चिम बंगाल में जनता तृणमूल कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। इस बार के विधानसभा चुनावों में जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। आने वाली 2 मई को पश्चिम बंगाल में 'असोल परिबर्तन' होने जा रहा है।

बी. एल. संतोष

इसलिए शरद पवार ने जूलियस रिबेरो की अगुवाई वाले जांच दल द्वारा जांच की मांग की है...उनके द्वारा समर्थित इस बेशर्म गठबंधन को अपराधबोध बिल्कुल ही नहीं है। एक कार्यरत पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड पर बताता है कि उसने शरद पवार को सूचित किया था और यहां आप अपने पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं।

थावरचंद गेहलोत

श्री नरेन्द्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। उन्होंने जो कहा उस पर लगातार अमल किया जा रहा है। इसके अनेक उदाहरण हैं और मोदी सरकार ने इस हेतु कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
चैत्र नवरात्रि (13 अप्रैल)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

पांचों राज्यों में भाजपा की लहर

जैसे-जैसे असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी एवं केरल में चुनाव प्रचार तेज हो रहा है, भाजपा के पक्ष में जनसमर्थन भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पूरे देश की आशा एवं विश्वास की एक नई किरण बनकर उभरी है। भाजपा के प्रति बढ़ता जन-समर्थन रैलियों एवं जनसभाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जिससे इन पांचों राज्यों में बहते चुनावी बयार को समझा जा सकता है। अपार उत्साह, आशा एवं अपेक्षा, भाजपा पर अटूट विश्वास तथा सकारात्मक वातावरण लोगों के नए आत्मविश्वास एवं भारतीय लोकतंत्र की सफलता का जीता-जागता उदाहरण है। ऐसा लगता है कि लोग यह समझ चुके हैं कि भारत का समय आ चुका है और उन्हें भारत उदय की इस प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए मतदान करना है जिससे 'आत्मनिर्भर भारत' का स्वप्न साकार हो सके। इन पांच राज्यों में हो रहे चुनावों में लोग 'नए भारत' के निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बनने के लिए तत्पर हैं।

भाजपा ने असम, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु के लिए अपना 'संकल्प-पत्र' जारी कर दिया है। असम के लिए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 'संकल्प-पत्र' जारी कर दस प्रमुख प्रतिबद्धता के जरिए प्रदेश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। पिछले पांच वर्षों में अनेक मजबूत एवं अभिनव प्रयासों के द्वारा भाजपा ने असम में शांति, विकास एवं प्रगति का युग प्रारंभ किया है। परिणामस्वरूप प्रदेश में भाजपा के प्रति जनसमर्थन तेजी से बढ़ा है। अब जबकि लोग असम में पुनः भाजपा सरकार चुनने का मन बना चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले दिनों में भाजपा 'संकल्प-पत्र' से एक 'आत्मनिर्भर असम' का निर्माण होगा।

पश्चिम बंगाल के लिए 'संकल्प-पत्र' केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने जारी कर 'सोनार बांग्ला' के स्वप्न को साकार करने के भाजपा के संकल्प को सुदृढ़ किया है। इस 'संकल्प-पत्र' में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं आयुष्मान भारत जैसे जनहितकारी केंद्रीय योजनाएं जिनसे तृणमूल सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को अब तक वंचित रखा गया है, उन्हें लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इस 'संकल्प-पत्र' में अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख है जिससे कांग्रेस-वामदलों-तृणमूल के दशकों के भ्रष्टाचार, लूट, विकास-विरोधी एवं गुंडागर्दी की राजनीति को खत्म कर प्रदेश में विकास एवं प्रगति के नए वातावरण का निर्माण होगा। यह एक ऐसा विस्तृत संकल्प है जिससे वंचित, शोषित, किसान, मजदूर, अनु.जा. एवं अनु.जन.जा., पिछड़ा वर्ग, महिला एवं युवा का नए अवसरों के निर्माण के माध्यम से व्यापक सशक्तिकरण होगा।

पांच राज्यों में हो रहे चुनावों में लोग 'नए भारत' के निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बनने के लिए तत्पर हैं

तमिलनाडु के लिए 'संकल्प-पत्र' केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा जारी किया गया जिसमें समाज के हर वर्ग के लिए भविष्योन्मुखी योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। एक ओर जहां कृषि के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी ओर 50 लाख रोजगार, घर पर राशन पहुंचाने, छात्रों के लिए लैपटॉप, हर जिले में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने का भी संकल्प है।

भाजपा एक ऐसी राजनैतिक पार्टी है जो जनता पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि जन-जन की सेवा करने के लिए सरकार बनाती है। भाजपा कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास एवं नेतृत्व की अटूट प्रतिबद्धताओं के कारण वे कार्य भी सिद्ध हुए हैं जो कुछ वर्ष पहले तक असंभव लगते थे। अब जबकि वैश्विक महामारी का एक वर्ष पूर्ण हो चुका है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के प्रति जनविश्वास देश के कोने-कोने में पहले से कई गुना अधिक बढ़ा है। 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान से देश में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है और अब हर कोई सफलता की कोई नई कहानी लिखने को तत्पर है। सकारात्मकता, आशा एवं विश्वास तथा विपरीत परिस्थितियों में भी विजय का संकल्प अब श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की पहचान बन चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके नेतृत्व में देश सफलता की नई गाथाएं लिख रहा है। इन पांच प्रदेश के चुनावों में जनता भाजपा को अपना भरपूर आशीर्वाद देकर और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प ले चुकी है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

विशाल जनसभा, करीमगंज (पश्चिम बंगाल)

"असम की भाजपा सरकार ने लाखों भूमिहीन साथियों को पट्टे दिए हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए अनेक नए स्कूल खोले हैं और ये काम लगातार चल रहा है"

आज असम में विकास और विश्वास की लहर है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 मार्च, 2021 को असम के करीमगंज में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश में विकास की गति को और तेज करने एवं असम को देश का एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए राज्य की जनता से पिछली बार से भी अधिक सीटों पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों और उनकी नीतियों ने असम को सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक हर तरह से नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस की सरकारें बराक वैली के लिए डिविजनल कमिश्नर गुवाहाटी से चलाती रहीं, ये कितना बड़ा अन्याय था। हमारी सरकार ने इस अन्याय को दूर किया। आज असम में विकास की लहर है, विश्वास की लहर है। आज असम में शांति का विश्वास है, समृद्धि का विश्वास है। आज असम में एक ही मुद्दा है- विकास, तेज़ विकास, निरंतर विकास, सबका विकास।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम की जनता से पूछते हुए कहा कि:

- बरसों से अटके हुए भारत के सबसे लंबे ब्रिज- भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किसने पूरा करवाया?– भाजपा की ही सरकार ने।
- असम को मेघालय से जोड़ने के लिए इससे भी बड़े धुबरी-फूलबारी ब्रिज का निर्माण कौन करवा रहा है? – भाजपा की सरकार।
- देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे असम को किसने दिया? – भाजपा की सरकार ने।
- किसने बरसों से अधूरे पड़े भारत के सबसे लंबे रेल-रोड ब्रिज- बोगीबील ब्रिज का काम पूरा करवाया? – भाजपा की सरकार ने।

उन्होंने कहा कि असम की भाजपा सरकार ने लाखों भूमिहीन साथियों को पट्टे दिए हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए अनेक नए स्कूल खोले हैं और ये काम लगातार चल रहा है। टी गार्डन में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं को हज़ारों रुपए की मदद दी जा रही है, ताकि वो खुद की और बच्चों की सेहत का ध्यान रख सकें। हाल में केंद्र सरकार ने बजट में चाय बगान में काम करने वाले साथियों के लिए 1000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया है।

श्री मोदी ने कहा कि दशकों से नॉर्थ-ईस्ट को जिस तरह विकास में नजरअंदाज किया गया, भाजपा सरकारें उसे मिलकर सुधार रही हैं। ■

'दीदी बोले खेला होबे, भाजपा बोले विकास होबे'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 मार्च, 2021 को पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश की जनता से हिंसा की राजनीति करने वाली भ्रष्टाचारी तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।

श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं। ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरह समझ रही हैं, इसलिए वह कह रही हैं, खेला होबे। जब जनता की सेवा की प्रतिबद्धता हो, जब बंगाल के विकास के लिए दिन-रात एक करने का संकल्प हो तो खेला नहीं खेला जाता, दीदी।

- दीदी बोले खेला होबे, भाजपा बोले विकास होबे।
- दीदी बोले खेला होबे, भाजपा बोले शिक्षा होबे।
- दीदी बोले खेला होबे, भाजपा बोले महिला का उत्थान होबे।
- दीदी बोले खेला होबे, भाजपा बोले संपूर्ण विकास होबे।
- दीदी बोले खेला होबे, भाजपा बोले सोनार बांग्ला होबे।
- दीदी बोले खेला होबे, भाजपा बोले नौकरी होबे।
- दीदी बोले खेला होबे, भाजपा बोले अस्पताल होबे।
- दीदी बोले खेला होबे, भाजपा बोले नौकरी होबे।
- दीदी बोले खेला होबे, भाजपा बोले स्कूल होबे।

श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नीति है – डीबीटी (DBT) अर्थात् 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' जबकि पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुर्नीति है – टीएमसी (TMC) – यानी 'ट्रांसफर माय कमीशन'। क्या हालत बना दी है दीदी ने बंगाल की?

पश्चिम बंगाल में जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, तब यहां विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान बनेगा

- क्राइम है, क्रिमिनल है लेकिन जेल में नहीं है!
- माफिया हैं, घुसपैठिए हैं लेकिन खुलेआम घूम रहे हैं!
- सिंडिकेट है, स्कैम है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती।

उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्वों के सपनों के 'सोनार बांग्ला' का फिर से निर्माण करना है।

- वह सोनार बांग्ला, जहां बंगाल के स्वर्णिम गौरव का समावेश होगा और आत्मनिर्भर का सामर्थ्य होगा।
- वह सोनार बांग्ला जहां हर गरीब, मजदूर, आदिवासी, किसान भाई-बंधु एक सम्मानित जीवन जिए।
- वह सोनार बांग्ला जहां की मां-बहन-बेटी सब सुरक्षित और भयमुक्त रहें।
- वह सोनार बांग्ला जहां के युवाओं के पास शिक्षा और रोजगार के भरपूर अवसर हों।
- वह सोनार बांग्ला जहां उद्योगों की कोई कमी न हो।
- वह सोनार बांग्ला जहां तोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट जैसे भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह न हो।
- वह सोनार बांग्ला जहां गुंडे-अपराधी, उग्रवादियों की जगह जेल में हो, सड़कों पर नहीं।

श्री मोदी कहा कि पश्चिम बंगाल में जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, तब यहां विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान बनेगा। ■

धकुआखाना, सूतिया और बारसोला (असम)

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 15 मार्च, 2021 को असम के धकुआखाना, सूतिया और बारसोला में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और कहा कि असम में इस बार पिछली बार से भी अधिक सीटों पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रही है।

श्री नड्डा ने कहा कि ऐसी मीडिया रिपोर्टें हैं कि कांग्रेस ने असम में पांच गारंटी दी है। आज तक कांग्रेस ने कोई वादा तो पूरा किया नहीं, लेकिन मैं कांग्रेस की तरफ से आप लोगों को एक गारंटी जरूर देना चाहता हूं। कांग्रेस कुछ करे या न करे लेकिन एक काम जरूर करेगी और वह है - घोटाला, घोटाला और घोटाला। कांग्रेस का मिशन कमीशन है जबकि भारतीय जनता पार्टी का मिशन है जनता की सेवा करना - यही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बुनियादी अंतर है।

असम में कांग्रेस-एआईयूडीएफ गठजोड़ पर जोरदार हमला बोलते हुए श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बड़ी ही निराली पार्टी है, सत्ता पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। 2006 में असम के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता तरुण गोगोई जी ने जिसके बारे में कहा था - हू इज बदरूद्दीन अजमल? आज कांग्रेस पार्टी उसे ही झुककर सलाम करती है और उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कितनी चोट पहुंचती होगी तरुण गोगोई जी की आत्मा को। पता नहीं, उनके पुत्र क्या सोचते हैं। खैर, यह वे जाने या उनका कांग्रेसी कुनबा जाने। कांग्रेस पर हमले की धार को और तेज करते हुए उन्होंने कहा कि केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हैं तो पश्चिम बंगाल में वे दोनों गले मिल रहे हैं। वहीं असम में कांग्रेस, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की न तो नीति स्पष्ट है, न सही नीयत है।

श्री नड्डा ने कहा कि असम में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले पांच वर्षों में विकास करके दिखाया है। यदि हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पांच वर्षों में असम को सुरक्षित कर सकते हैं, आतंकवाद, घुसपैठ और आंदोलनों से मुक्त बना सकते हैं तो अगले पांच वर्षों में हम असम को बाढ़ मुक्त भी बना सकते हैं और इसे विकसित राज्य भी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में असम में 6 नए मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई है। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मैंने गुवाहाटी से 150 से अधिक मोबाइल डिस्पेंसरी को जनता की सेवा में समर्पित किया था, जो आज चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य का बहुत बड़ा सहारा बनी है। प्रधानमंत्री जी ने चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के परिवार के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। तेजपुर में कैंसर सेंटर खुला है तो बरसोला में आजादी के 70 साल में पहली बार डिग्री कॉलेज खुला है। असम को 15 हाइवे की सौगात दी गई है तो रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए भी 8,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। देश में जहां-जहां भी भाजपा-एनडीए की सरकार है, विकास जमीन पर

उतरा है क्योंकि विकास, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा है।

उन्होंने कहा कि 60 साल कांग्रेस के एक तरफ रख दीजिए और 60 महीने सर्बानंद जी के नेतृत्व में चलने वाली असम की एनडीए की सरकार को रख दीजिए। आप पाएंगे कि 60 महीने वाला पलड़ा, 60 साल वाले पलड़े से कहीं भारी साबित होगा। 6,000 करोड़ रुपये की लागत वाला

शन कमीशन, सेवा: जगत प्रकाश नड्डा

तय हुआ कि बोडो जनता असम में ही भाईचारे के साथ रहेंगे और उनका भी विकास किया जायेगा। इस समझौते के तहत अलगाववादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफ़बी) के सभी चार गुटों ने आत्मसमर्पण किया, 4,000 से ज्यादा एसोल्ट राइफल सरेंडर किये गए, 2,300 लोग गिरफ्तार हुए। बोडो लोगों के विकास और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराकर असम को शांत और भयमुक्त कराने का काम सफलतापूर्वक कर दिखाया।

देश में जहां-जहां भी भाजपा-एनडीए की सरकार है, विकास जमीन पर उतरा है क्योंकि विकास, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा है

बोगिविल ब्रिज कांग्रेस की नीति के कारण लटका और अटका हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और श्री सर्बानंद सोनोवाल के प्रयासों से इस ब्रिज का निर्माण संपन्न हो पाया। इसी तरह, धुबरी-फूलबाड़ी ब्रिज का निर्माण भी कई वर्षों से अटका हुआ था। धुबरी-फूलबाड़ी का निर्माण भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और श्री सर्बानंद सोनोवाल के प्रयासों से संपन्न हो पाया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयास से 1032 करोड़ रुपये की लागत से गुवाहाटी एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है। असम के लोग इलाज के लिए दिल्ली का एम्स जाया करते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आशीर्वाद से जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना और अब गुवाहाटी में एम्स बनकर तैयार हो रहा है।

श्री नड्डा ने बाढ़ मुक्त असम की बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम को बाढ़ मुक्त करने के लिए चार गुना अधिक धनराशि दी है। अब असम बाढ़ मुक्त होगा। एरियल सेटेलाइट के माध्यम से सर्वे हो रहा है। जहां-जहां बाढ़ का पानी आता है, वहां बड़े-बड़े तालाब बनेंगे जिसमें मछली पालन होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 60 सालों के कुशासन में असम बोडो उग्रवादियों की हिंसा से त्रस्त रहा, इन हिंसा में चार हजार से ज्यादा लोग मारे गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 27 जनवरी, 2020 को बोडोलैंड समझौता कराया जिसमें

श्री नड्डा ने कहा कि असम के साथ प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है। इस बार के बजट में 53,000 करोड़ रुपये असम के विकास के लिए दिए गए हैं। 35,000 करोड़ रुपये 1,500 किमी नेशनल हाईवे बनाने के लिए दिए गए हैं। पिछले 25 सालों से दर-दर भटकने को विवश लगभग 35,000 लोगों को प्रभावित करने वाले ब्रू - रियांग संकट को सुलझा लिया गया है और इन लोगों के लिए 600 करोड़ रुपये उपलब्ध कराकर इन्हें मुख्यधारा में लाने का काम किया जा रहा है।

श्री नड्डा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान महज एक नारा नहीं बल्कि एक अभियान है जिसके तहत पूरे देश में 11 करोड़ और सिर्फ असम में 60 लाख शौचालय बने। उज्ज्वला योजना के तहत देश में 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। उस में से 36 लाख कनेक्शन असम में दिए गए। उजाला योजना के तहत 67 लाख एलईडी बल्ब वितरीत किये गए. आयुष्मान भारत योजना के 1.60 करोड़ लाभार्थियों में से 1.38 लाख लाभार्थी असम के हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पूरे देश में 11 करोड़ 70 लाख किसान और असम के 16 लाख किसान लाभान्वित हुए। ■

'ममता दीदी, आपका जाना और राज्य में कमल खिलना तय है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 16 मार्च, 2021 को कोतुलपुर, पश्चिम बंगाल में आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित किया और पश्चिम बंगाल की जनता से भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति करने वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकते हुए पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का आह्वान किया।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश के गांव, गरीब और किसान के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सार्थक प्रयास किया है जो जमीन पर दिखाई दे रहा है। स्वच्छ भारत योजना हो, जन-धन योजना हो, सौभाग्य योजना हो, सामाजिक सुरक्षा कवच की योजनाएं हों, आयुष्मान भारत हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि - ये सभी योजनाएं देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित - सबके जीवन में उत्थान का कारक बनी हैं, लेकिन आपको यह बताते हुए मुझे अतिशय पीड़ा हो रही है कि पश्चिम बंगाल के गरीब अब तक आयुष्मान भारत की योजना का लाभ लेने से वंचित हैं, यहां के किसानों को अब तक किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं मिल पाया है क्योंकि गरीब एवं किसान विरोधी ममता बनर्जी सरकार इन योजनाओं के जनता तक पहुंचने के मार्ग में रोड़ा बन कर खड़ी है। ममता दीदी, आपका जाना और पश्चिम बंगाल में कमल खिलना तय है।

यदि पश्चिम बंगाल से टोलाबाजी शेष करना है, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार ख़त्म करना है और भय मुक्त बंगाल बनाना है तो कमल खिलाना होगा

श्री नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तुष्टिकरण की राजनीति का आलम यह है कि यहां ओबीसी आरक्षण में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को भी जोड़ दिया गया लेकिन ममता दीदी ने हिंदू धर्म की ओबीसी जातियों महिस्या एवं तेली को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा। भाजपा की सरकार बनने पर इसके लिए एक कमीशन बनाया जाएगा और आरक्षण के लाभ से वंचित महिस्या एवं तेली जातियों को भी इस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। इसके तहत मंडल कमीशन के अनुसार लिखित जातियों को आरक्षण के दायरे में लाया जाएगा।

बाटला हाउस एनकाउंटर की चर्चा करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि 13 साल पहले दिल्ली में जामिया नगर के बाटला हाउस में आतंकियों के साथ दिल्ली पुलिस के जवानों की मुठभेड़ हुई थी जिसमें दिल्ली पुलिस के जांबाज इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी शहीद हो गए थे जबकि इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी आरिज खान फरार हो गया था। तब ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर फेक है और यदि ये एनकाउंटर फेक नहीं हुआ तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगी। 13 साल बाद सभी साक्ष्यों के मद्देनजर कोर्ट ने आरिज खान को आतंकी करार देते हुए बम धमाकों एवं शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या का दोषी पाया है और उसे फांसी की सजा सुनाई है। ममता दीदी, पश्चिम बंगाल की जनता आपसे पूछ रही है कि आप राजनीति से संन्यास कब लेंगी। आप संन्यास लें न लें लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता आपकी राजनीति से संन्यास लेने पर मजबूर जरूर कर देगी। आज आपको न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि समग्र राष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

श्री नड्डा ने पश्चिम बंगाल की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि यदि पश्चिम बंगाल से टोलाबाजी शेष करना है, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार ख़त्म करना है और भय मुक्त बंगाल बनाना है तो कमल खिलाना होगा। ■

'एनडीए सरकार ने असम के विकास की एक ठोस नींव रखी है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 मार्च, 2021 को असम में तिनसुकिया के चाबुआ में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और असम में बीते पांच वर्षों में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए प्रदेश की जनता से एक बार पुनः पूर्ण बहुमत से भाजपानीत एनडीए सरकार बनाने का आह्वान किया।

श्री मोदी ने असम की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हाल में आपने भी एक टूलकिट की चर्चा सुनी होगी। इस टूलकिट में असम की चाय और हमारे योग को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। टूलकिट बनाने वाले चाहते हैं कि हमारे चाय बगानों को भारी नुकसान उठाना पड़े। ऐसी साजिश रचने वालों को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस असम के लोगों से बहुत दूर हो चुकी है। अभी 2-3 दिन पहले इन लोगों ने श्रीलंका की एक फोटो दिखाई और कहा कि ये असम है! कुछ हफ्ते पहले इन लोगों ने 'ताइवान' की फोटो दिखाई और कहा कि ये असम है! गलती एक बार हो सकती है लेकिन गलती दोहराई जाए तो वो गलती नहीं, प्रवृत्ति होती है। ये असम की खूबसूरती के साथ अन्याय और इसका अपमान है।

आपको याद रखना है कि कांग्रेस अपने फायदे के लिए किसी को भी दांव पर लगा सकती है। उसे असम के लोगों की चिंता नहीं, कुर्सी की चिंता ज्यादा है

उन्होंने कहा कि टी गार्डेन्स में काम करने वाले श्रमिक साथियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए एनडीए सरकार का अभियान और तेज किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले पांच सालों में यहां एनडीए सरकार ने असम के विकास की एक ठोस नींव रखी है। अब उस नींव पर असम के तेज़ विकास की सशक्त इमारत खड़ी करने का समय है। कांग्रेस और उसके साथी इसी समय का लाभ उठाना चाहते हैं। बीते पांच वर्षों में असम ने जो हासिल किया है, अब वो उसे लूटना चाहते हैं। आपको संभलकर रहना है, सतर्क रहना है। आपको याद रखना है कि कांग्रेस अपने फायदे के लिए किसी को भी दांव पर लगा सकती है। उसे असम के लोगों की चिंता नहीं, कुर्सी की चिंता ज्यादा है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि जहां एक ओर हमारी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के पवित्र मंत्र पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आज झूठी घोषणाओं का भोंपू बनकर रह गई है। उसकी ये सच्चाई देश भर के लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, आज सिमटती जा रही है। कारण बिल्कुल साफ है। कांग्रेस में प्रतिभा के प्रति सम्मान नहीं है, सत्ता का लालच सर्वोपरि है। सत्ता के लिए ये किसी का भी साथ ले सकते हैं, किसी का भी साथ दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि असम में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की, एनडीए सरकार की निरंतर जरूरत है। ये समय असम के भविष्य के लिए बहुत अहम है। ये समय आत्मविश्वास का है, आत्मनिर्भरता का है। असम की जनता को याद रखना है कि ये वही कांग्रेस है जिसने मूल निवासियों को जमीन का अधिकार देने के लिए कभी भी गंभीर कदम नहीं उठाए। यहां के मूल निवासियों को जमीन के पट्टे देने का काम सीएम सर्बानंद जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने ही शुरू किया। ■

'दीदी की पार्टी निर्ममता की पाठशाला है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 मार्च, 2021 को पश्चिम बंगाल में खड़गपुर के बीएनबी ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और विकास एवं भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर तृणमूल कांग्रेस एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश की जनता से तुष्टिकरण और टोलाबाजी करने वाली तृणमूल सरकार की जगह पश्चिम बंगाल के विकास के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का उत्साह कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा सरकार। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री दिलीप घोष के अथक प्रयासों की भी सराहना की।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज दीदी ओंगीकार (अंगीकार) की बात कर रही हैं। दीदी, पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको दस वर्षों तक सेवा का अवसर दिया लेकिन आपने उन्हें लूट-मार से भरे दस साल दिए, आपने उन्हें 10 साल का भ्रष्टाचार दिया, आपने उन्हें 10 साल का कुशासन दिया। उन्होंने कहा कि कल रात को 50-55 मिनट के लिए व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन हो गया, लोग अधीर हो उठे लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में तो 50-55 साल से विकास डाउन है, सपने डाउन हो गए हैं, संकल्प ही डाउन हो गया है। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और अब तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के विकास को अवरुद्ध करके रखा है। दीदी का भी ट्रैक रिकॉर्ड दलित, आदिवासी, पिछड़ों का हक छीनकर तुष्टिकरण करने का है। दीदी ने बंगाल की युवा पीढ़ी के बहुत कीमती 10 साल छीन लिए हैं। दीदी की सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में आनाकानी कर रही है। दीदी को पश्चिम बंगाल के लाखों युवाओं के भविष्य की, उनके करियर की कोई चिंता नहीं है। आपने 70 साल तक अनेक को देखा, हम वादा करते हैं कि एक बार आशीर्वाद दीजिए हम आपकी भलाई के लिए अपनी जान खपा देंगे। मैं पश्चिम बंगाल के युवाओं को भरोसा देता हूं कि दीदी को बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा।

पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और अब तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के विकास को अवरुद्ध करके रखा है

श्री मोदी ने कहा कि दीदी की पार्टी निर्ममता की पाठशाला है। इस पाठशाला का सिलेबस है - टोलाबाजी, कटमनी और भ्रष्टाचार। यहां शिक्षा की स्थिति क्या है, यह खड़गपुर के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। दीदी कह रही है खेला होबे। पश्चिम बंगाल कह रहा है खेला शेष होबे, विकास आरंभ होबे। आज दीदी से पश्चिम बंगाल के नागरिक दस साल का हिसाब मांग रहे हैं लेकिन जवाब देने की बजाय दीदी उन पर अत्याचार कर रही है।

श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ देश निरंतर सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है ताकि उद्यमियों एवं कारोबारियों को यहां-वहां भटकना ना पड़े, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया है। ये सिंगल विंडो है- भाइपो विंडो। पश्चिम बंगाल में इस विंडो से गुज़रे बिना कुछ नहीं हो सकता। पिछले 10 साल में तृणमूल सरकार ने हर वो काम किया जो यहां रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को रोकने वाला था। तृणमूल कांग्रेस के वसूली गिरोहों, सिंडिकेट के कारण अनेक पुराने उद्योग बंद हो गए। यहां सिर्फ एक ही उद्योग चलने दिया गया है और वह है - माफिया उद्योग। सुबर्णरेखा नदी और कंसावती नदी में अवैध खनन के तार कहां से जुड़े हैं, ये यहां का बच्चा-बच्चा जानता है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इन सभी पर सख्त कार्रवाई होगी, कानून का राज स्थापित किया जाएगा। ■

भाजपा तुष्टिकरण की राजनीति और घुसपैठ की समस्या को ख़त्म करके रहेगी: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 21 मार्च को पश्चिम बंगाल के एगरा (पूर्वी मेदिनीपुर) में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश की जनता से तृणमूल की भ्रष्टाचारी और अराजक सरकार को जड़ से उखाड़ कर विकास के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आह्वान किया। श्री शाह की उपस्थिति में एगरा की जनसभा में तृणमूल कांग्रेस से सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री सुवेंदु अधिकारी के पिताजी श्री शिशिर अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित थे।

पश्चिम बंगाल की जनता एक बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर दे, हम टोल मनी और कट मनी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे

श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यहां पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा करने के लिए अदालत की परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा करने पर शिक्षकों को मारा जाता है। बंगाली भाषा की बात करने वाले शिक्षकों पर पुलिस द्वारा गोली चलायी जाती है। पश्चिम बंगाल की जनता एक बार प्रदेश में कमल की सरकार बनाएं, यहां की धरती पर दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा को कोई नहीं रोक पायेगा।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता को हर काम में टैक्स मनी देना पड़ता है। तृणमूल सरकार में सरेआम टोलाबाजी हो रही है। ममता दीदी कहती हैं कि किसी काम के लिए 500 रुपये लिए जाते हैं उसमें क्या हो गया? ममता दीदी, आपकी बात अलग है। भतीजे का कट मनी आपके पास आता है लेकिन पश्चिम बंगाल के मजदूर के लिए 500 रुपये बहुत बड़ी चीज होती है। कट मनी और टोलाबाजी बंद होनी चाहिए। ममता दीदी कहती हैं कि 500 रुपये में क्या होता है जबकि हम कहते हैं कि पांच आने भी टोल मनी और कट मनी में पश्चिम बंगाल की जनता का नहीं जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनता, एक बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर दें, हम टोल मनी और कट मनी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे।

श्री शाह ने कहा कि ममता दीदी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 'सोनार बांग्ला' का निर्माण करना चाहते हैं। ये पश्चिम बंगाल की जनता को तय करना है कि उन्हें किसी 'भतीजे' को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करना है या 'सोनार बांग्ला' के निर्माण के लिए वोट डालना है। यदि पश्चिम बंगाल को 'सोनार बांग्ला' बनाना चाहते हैं तो भाजपा की सरकार बनाइये।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दे दिया जाएगा। हम शिक्षकों के वेतन को भी बढ़ाएंगे।

श्री शाह ने कहा कि हमने तय किया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर हम माहिस्य समाज को ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ देंगे। साथ ही, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। हम ऐसे सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए कृतसंकल्पित हैं जहां रोजगार के लिए बंगाल के युवाओं को पलायन न करना पड़े। पश्चिम बंगाल में बनने वाली भाजपा सरकार तुष्टिकरण की राजनीति और घुसपैठ की समस्या को ख़त्म करके रहेगी। ■

असम विस चुनावः भाजपा संकल्प-पत्र

शिक्षा एवं रोजगार पर जोर

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 23 मार्च, 2021 को असम के विकास के रोडमैप हेतु भाजपा–नीत एनडीए का 'संकल्प पत्र' जारी किया। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री रणजीत दास, असम के स्वास्थ्य मंत्री एवं नेडा के चेयरमैन श्री हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के भाजपा प्रभारी श्री बैजयंत जय पांडा, केंद्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दिलीप सैकिया और पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं बिहार सरकार में मंत्री श्री सैयद शाहनवाज हुसैन सहित सभी वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी एवं मीडिया बंधु उपस्थित थे।

उम्मीदों एवं आकांक्षाओं के साथ असम की जनता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए भाजपा ने लिये 10 संकल्प

मिशन ब्रह्मपुत्रः हम बाढ़ मुक्त असम के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। असम की अगली भाजपा सरकार मिशन ब्रह्मपुत्र योजना शुरू करेगी ताकि सालाना आने वाली बाढ़ के चलते जान माल की रक्षा की जा सके। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के अधिक पानी को स्टोर करने के लिए रिजरवायर बनाया जाएगा। साथ ही धुबरी से सादिया तक नदी के भीतर विशेष मशीन से कचड़े की सफाई की जाएगी।

महिला सशक्तिकरणः हम महिला सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्पित हैं। हम 30 लाख गरीब परिवारों को अरुणोदय स्कीम के तहत कवर करेंगे। इस स्कीम के तहत फिलहाल मिल रही मासिक आर्थिक सहायता राशि को 830 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये मासिक किया जाएगा।

असम की संस्कृति का संरक्षणः असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश के सभी नामघरों और सत्र भूमि का संरक्षण करने के लिए कटिबद्ध है। आदिवासी समुदायों के पूजा स्थलों को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए एक टास्क फ़ोर्स का गठन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक नामघर को ढाई-ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

मिशन शिशु उन्नयनः मिशन शिशु उन्नयन के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों में हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। असम में पुनः भाजपा सरकार बनने पर 8वीं कक्षा से हर स्कूली बच्चे को साइकिल दी जायेगी।

एनआरसीः असम में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार सही एनआरसी लागू करेगी, ताकि भारतीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके और अवैध घुसपैठियों को इससे बाहर किया जा सके।

परिसीमनः हम असम के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए परिसीमन करेंगे।

असम आहार आत्मनिर्भर योजनाः असम में भाजपा सरकार बनने पर असम आहार आत्मनिर्भर योजना शुरू की जाएगी। हम असम में खाद्य सामग्रियों, खास तौर से मछली, हॉर्टीकल्चर, पोल्ट्री, डेयरी और बागवानी उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

रोजगारः हम असम के युवाओं को दो लाख सरकारी नौकरियां देंगे। इनमें से एक लाख नौकरियां तो सरकार बनने के एक साल के अंदर अर्थात् 31 मार्च, 2022 से पहले-पहले दे दी जायेगी। निजी क्षेत्र में भी 8 लाख नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी।

उद्यमः असम में भाजपा सरकार बनने पर स्वामी विवेकानंद असम यूथ एंप्लॉयमेंट योजना के तहत हर वर्ष दो लाख अर्थात् पांच वर्षों में 10 लाख युवा उद्यमियों को तैयार किया जाएगा, ताकि व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो सकें।

जमीन का अधिकारः हम प्रदेश के सभी भूमिहीन व्यक्तियों को जमीन के पट्टे देंगे और उनका सशक्तिकरण करेंगे। ■

पश्चिम बंगाल विस चुनावः सोनार बांग्ला संकल्प-पत्र

ऐ बार सोनार बांग्ला, ऐ बार आशोल पोरिबोर्तन, ऐ बार बीजेपी

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 21 मार्च, 2021 को पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का 'सोनार बांग्ला संकल्प पत्र' जारी किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र तैयार करने के लिए पूरे बंगाल में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और राज्य की जनता से प्रदेश में बदलाव को लेकर राय मांगी थी। इस अभियान की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने की थी। पार्टी ने इस अभियान का नाम 'लोक्खो सोनार बांग्ला अभियान' दिया था। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने हर विधान सभा क्षेत्र में एक-एक एलईडी रथ पहुंचाने के लिए 294 एलईडी रथों की व्यवस्था की थी। साथ ही, प्रमुख स्थानों पर सुझाव हेतु बक्से भी रखे गए थे। वेबसाईट, मिस्ड कॉल और व्हाट्सअप के माध्यम से भी राज्य के लोगों से सुझाव मांगे गए थे। पश्चिम बंगाल के नागरिकों के सुझावों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना 'सोनार बांग्ला संकल्प पत्र' तैयार किया जिसे कोलकाता के ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में खचाखच भरे संवाददाता सम्मेलन में जारी किया। श्री शाह ने भाजपा का 'सोनार बांग्ला संकल्प पत्र' जारी करते हुए कहा कि हमारे संकल्प पत्र का मूल आधार 'सोनार बांग्ला' की परिकल्पना है। यह सिर्फ घोषणा नहीं है, हमारा संकल्प है। ऐ बार सोनार बांग्ला, ऐ बार आशोल पोरिबोर्तन, ऐ बार बीजेपी।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में बनने वाली भाजपा सरकार राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देगी। केजी से पीजी तक महिलाओं की पढ़ाई फ्री होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनका सफर भी फ्री रहेगा। महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा की सुविधा उपलब्ध की जायेगी।
- बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर किसान सम्मान निधि में 75 लाख किसानों को 18 हजार रुपए एक साथ (पिछली किस्तों की राशि के साथ अगली क़िस्त मिलाकर) बिना कटमनी के उनके खाते में दिए जाएंगे। भूमिहीन किसानों और मछुआरों को 3 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। मछुआरे भाइयों को भी सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जायेगी।
- हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- पीडीएस घोटाला, चिट फंड घोटाला, बिस्वा बांग्ला घोटाला, मेट्रो डेयरी घोटाला सहित सभी मेगा घोटाले की जांच के लिए एसआईटी की स्थापना की जायेगी। राजनीतिक हत्याओं की जांच के लिए एसआईटी की स्थापना की जायेगी और राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 25 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा।
- पश्चिम बंगाल में बनने वाली भाजपा सरकार सोनार बांग्ला Economic Revival Task Force की स्थापना करेगी।
- घरेलू खपत के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जायेगी।
- बांग्ला भाषा को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया जाएगा।
- बंगाल में हमारी सरकार आने पर दिन में तीन बार केवल पांच रुपये में पोषक भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा कैंटीन की स्थापना की जायेगी।
- सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू करेंगे। मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को पांच साल तक डीबीटी से 10 हजार रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा। मतुआ दलपतियों के लिए 3,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था की जायेगी।
- पहली कैबिनेट बैठक में ही सातवें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा।
- घरेलू खपत के लिए 200 यूनिट तक के उपयोग के लिए मुफ्त बिजली और शहर में घरों में 24x7 बिजली की आपूर्ति की जायेगी। ■

50 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का संकल्प

केंद्रीय मंत्री सर्वश्री नितिन गडकरी एवं वी. के. सिंह ने 22 मार्च, 2021 को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प-पत्र जारी किया। इस अवसर पर श्री एच. राजा, श्री शशिकला पुष्पा, श्री के. अन्नामलाई, श्री वी. पी. दुरीसामी और श्री एम. नचियप्पन उपस्थित थे। संकल्प-पत्र में पचास लाख नौकरियों, राशन की होम डिलीवरी, मछुआरों और किसानों के लिए 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता और राज्य में शराबबंदी का वादा किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री नितिन गडकरी ने कहा, "हमें पूरा विश्वास है कि तमिलनाडु में राजग को बहुमत मिलेगा। हमारे पास एक ऐसी सरकार होगी जो तमिलनाडु को एक प्रगतिशील राज्य के रूप में विकसित करेगी।"

प्रमुख बिंदु

- एनडीए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि व्यापार में सुगमता के मामले में तमिलनाडु नंबर एक राज्य बने।
- 18 से 23 वर्ष की महिलाओं को मुफ्त दोपहिया लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उन्हें ड्राइविंग टेस्ट देने और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
- कक्षा 8 और 9 के छात्रों को मुफ्त में 'टैबलेट' प्रदान किया जाएगा।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन का वितरण।
- प्रत्येक जिले को सरकारी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल मिलेगा जिसमें निजी अस्पतालों के बराबर सुविधाएं होंगी और मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।
- विधवाओं की पेंशन 3,000 रुपये तक बढ़ाई जाएगी।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के मछुवारों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- कृषि के लिए अलग बजट।
- बारह लाख एकड़ पंचमी भूमि को फिर से अनुसूचित जाति के लोगों को वितरित किया जाएगा।
- हिंदू मंदिरों का प्रशासन धार्मिक नेताओं के साथ एक बोर्ड को सौंपा जाएगा।
- भूजल और नदियों के प्रवाह में सुधार के लिए नदी से रेत खनन पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस अवधि के दौरान नदी की रेत को आयात करने की अनुमति होगी।
- ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन का विभाजन किया जाएगा।
- विषय विशेषज्ञों द्वारा विषयों पर बहस की सुविधा के लिए विधान परिषद की स्थापना की जाएगी।
- बदूगा को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में जोड़ा जाएगा।
- सभी राज्य राजमार्गों को चार-लेन की सड़कों में परिवर्तित किया जाएगा।
- हर जिले में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) के लिए कोचिंग सेंटर होंगे।
- ऑनलाइन कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
- कोयंबटूर में मद्रास उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच स्थापित की जाएगी।
- जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाया जाएगा।
- पलानी में सिद्ध चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- इरोड जिले में तिरुक्कुरल ममलाई पार्क की स्थापना की जाएगी।

भाजपा राज्य में एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है और 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही पार्टी कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी चुनाव लड़ रही है। ■

17 राज्यों ने 'वन नेशन, वन राशन' कार्ड प्रणाली को किया लागू

यह सुधार विशेष रूप से प्रवासी आबादी को सशक्त और खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाता है जो अक्सर अपना निवास स्थान बदलती रहती है

देश के 17 राज्यों ने 'वन नेशन, वन राशन' कार्ड प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन शुरू कर दिया है और उत्तराखंड इस तरह के सुधार को पूरा करने वाला हालिया राज्य बन गया। जो राज्य इस प्रणाली को पूरा कर रहे हैं वे राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25 प्रतिशत के अतिरिक्त ऋण के पात्र हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत इन राज्यों को वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए 37,600 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। 'वन नेशन, वन राशन' कार्ड सिस्टम नागरिक केंद्रित एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसके कार्यान्वयन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

यह सुधार विशेष रूप से प्रवासी आबादी को सशक्त और खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाता है जो अक्सर अपना निवास स्थान बदलती रहती है। इसमें ज्यादातर श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, शहरी गरीब, कबाड़ उठाने वाले, फुटपाथ पर रहने वाले, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के अस्थायी श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि शामिल हैं। प्रौद्योगिकी से संचालित यह सुधार प्रवासी लाभार्थियों को देश में कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) से समर्थ किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त करने में समर्थ बनाता है।

राशन कार्ड की निर्बाध अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी राशन कार्डों की आधार सीडिंग और स्वचालन के माध्यम से लाभार्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है।

साथ ही, सभी उचित मूल्य दुकानों (एफपीएस) पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणों को अनिवार्य तौर पर स्थापित किया गया है। इसलिए राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी सीमा की मंजूरी निम्नलिखित दोनों कार्यों के पूरा होने पर ही दी जाती है:

i. **राज्य में सभी राशन कार्ड और लाभार्थियों के आधार को लिंक करना**

ii. **राज्य के सभी एफपीएस का स्वचालन**

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने 17 मई, 2020 को राज्यों की कर्ज सीमा को उनके जीएसडीपी के 2 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था। इस विशेष व्यवस्था का आधा यानी जीएसडीपी का 1 प्रतिशत राज्यों द्वारा नागरिक केंद्रित सुधारों को लागू करने से जुड़ा था। व्यय विभाग द्वारा पहचान किए गए सुधार के चार नागरिक केन्द्रित क्षेत्र इस प्रकार हैं- (क) 'वन नेशन, वन राशन' कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन, (ख) कारोबारी सुगमता संबंधी सुधार, (ग) शहरी स्थानीय निकाय/यूटिलिटी सुधार और (घ) ऊर्जा क्षेत्र में सुधार। ■

20,000 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान की स्थापना के लिए विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी। इस संस्थान से देश में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि कोष बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 16 मार्च को बताया कि इसके लिए शुरुआती अनुदान पांच हजार करोड़ रुपये का होगा और इतनी ही राशि तक का अतिरिक्त अनुदान होगा।

उन्होंने बताया कि सरकार इस संस्थान को कुछ प्रतिभूतियां जारी करने पर भी विचार कर रही है, जिससे कोष की लागत कम हो सकेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को बाजार से बड़ी राशि प्राप्त होने की आशा है। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि संस्थान अगले कुछ वर्षों में तीन लाख करोड़ रुपये तक जुटा सकता है। संस्थान को दस साल की लम्बी अवधि के लिए कुछ कर लाभ दिए जाएंगे। ■

जीएसटी क्षतिपूर्ति हेतु जारी हुए 1.10 लाख करोड़ रुपये

भारत सरकार ने अक्टूबर, 2020 में जीएसटी राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए विशेष उधारी खिड़की की व्यवस्था की, जिसके तहत 1.10 लाख करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति का अनुमान लगाया गया था

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15 मार्च, 2021 को जीएसटी राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 20वीं और अंतिम साप्ताहिक किस्त के तहत 4,104 करोड़ रुपये जारी किए। जारी की गई राशि में से 4086.97 करोड़ रुपये 23 राज्यों को और 17.03 करोड़ रुपये की राशि 3 केंद्रशासित प्रदेशों को जारी की गई है। जिन केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा हैं।

20वीं किस्त जारी होने के साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति की 100 फीसदी राशि 1.10 लाख करोड़ रुपये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी कर दी गई है। इसके तहत 1,01,329 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को और 8,879 करोड़ रुपये की राशि विधानसभा वाले 3 केंद्रशासित प्रदेशों को जारी की गई है।

भारत सरकार ने अक्टूबर, 2020 में जीएसटी राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए विशेष उधारी खिड़की की व्यवस्था की, जिसके तहत 1.10 लाख करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति का अनुमान लगाया गया था। इसके लिए 23 अक्टूबर, 2020 से शुरू हुई कर्ज देने की प्रक्रिया अब 20वीं किस्त देने के बाद पूरी हो गई है।

इस विशेष खिड़की के तहत 3 साल और 5 साल की अवधि वाले सरकारी स्टॉक में भारत सरकार उधार लेती रही है। उधारी के तहत कर्ज की अवधि को राज्यों के लिए समान रूप से तय किया गया। जो कि राज्यों के जीएसटी राजस्व में आई कमी की भरपाई के आधार पर तय की गई थी।

मौजूदा किस्त जारी करने के बाद 5 साल और 3 साल के तहत बाकी राशि को देने का कार्य 23 राज्यों और विधानसभाओं वाले 3 केंद्रशासित प्रदेशों के लिए पूरा हो गया है, जबकि बचे 5 राज्यों के जीएसटी राजस्व में कमी नहीं आई है।

इस समय राज्यों को जो राशि जारी की गई, वह 20वीं किस्त है। केंद्र सरकार ने यह रकम इस हफ्ते 4.9288 फीसदी के ब्याज पर कर्ज के रूप में ली है। केंद्र सरकार ने विशेष उधार खिड़की के तहत कुल 1,10,208 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, जिस पर उसे औसतन 4.8473 फीसदी का ब्याज चुकाना होगा।

विशेष उधार खिड़की के द्वारा पूंजी चुकाने के साथ-साथ भारत सरकार ने जीएसटी लागू करने में आई राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.50 फीसदी अतिरिक्त राशि के रूप में उधार लेने का भी विकल्प दिया था। इसके लिए सभी राज्यों ने विकल्प-1 का चयन किया था। इसके तहत 28 राज्यों को 1,06,830 करोड़ (राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद का 0.50 फीसदी) की अतिरिक्त उधारी का भी प्रावधान किया गया है। इस कदम से राज्यों को पूंजी जुटाने का अतिरिक्त संसाधन भी उपलब्ध हुआ है। ■

पांच साल में 33 फीसदी कम हुआ भारत का हथियारों का आयात

भारत में 2011-15 और 2016-20 के बीच हथियारों के आयात में 33 फीसदी की कमी आई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) की 15 मार्च को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश की जटिल खरीद प्रक्रिया और रूसी हथियारों पर निर्भरता कम करने की कोशिशों के तहत भारतीय हथियार आयात में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 2011-15 और 2016-20 के बीच हथियारों के आयात में 33 फीसदी की कमी आई। रूस सर्वाधिक प्रभावित आपूर्तिकर्ता रहा, हालांकि अमेरिका से भी भारत में हथियारों के आयात में 46 फीसदी की कमी आई। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए, ताकि सैन्य साजो-सामान के आयात पर निर्भरता कम हो सके। भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपये के रक्षा कारोबार का लक्ष्य रखा है। ■

मोज़ाम्बिक को 3000 एचपी केप गेज लोकोमोटिव का निर्यात

भारतीय रेलवे 3000 एचपी गेज लोकोमोटिव के 6 लोकोमोटिव और 90 स्टेनलेस स्टील यात्री डिब्बों के कुल क्रम के हिस्से के रूप में 2 लोकोमोटिव के पहले बैच का निर्यात कर रहा है

केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 3000 एचपी केप गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। मोज़ाम्बिक को इंजनों के निर्यात से भारत-अफ्रीका संबंध और निर्यात के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

रेल मंत्रालय द्वारा 10 मार्च को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय रेलवे 3000 एचपी गेज लोकोमोटिव के 6 लोकोमोटिव और 90 स्टेनलेस स्टील यात्री डिब्बों के कुल क्रम के हिस्से के रूप में 2 लोकोमोटिव के पहले बैच का निर्यात कर रहा है।

इन लोकोमोटिव को मेक-इन-इंडिया मिशन के तहत बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इन्हें भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राइट्स लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया जा रहा है। 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना से इन्हें भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। साथ ही, यह भारत द्वारा वित्तपोषित किया गया है।

3000 एचपी केप गेज लोकोमोटिव की महत्वपूर्ण विशेषताएं

- यह लोकोमोटिव लेवल ट्रैक पर 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 2255 टन वजन ढोने की क्षमता और 400एन के अधिकतम ट्रैक्टिव प्रयास के लिए सक्षम है।
- इस लोकोमोटिव के केबिन शोर-कंपन और कर्कश ध्वनि-रोधी हैं, जहां वैज्ञानिक तकनीक से आवाज को बेहतर कर्णप्रिय बनाया गया है।
- इसकी सीटें भी बेहद आरामदायक हैं और इंटीग्रेटेड ग्राफिक ड्राइवर डिस्प्ले भी है। बेहतर क्रू कंफर्ट और थकान को कम करने के लिए हीटिंग वेंटिंग एसी भी दिया गया है।
- परिवहन के दौरान इस्तेमाल के लिए पानी की टंकी (टॉयलेट मॉड्यूल), रेफ्रिजरेटर और हॉट प्लेट की सुविधाएं भी हैं।
- राइट हैंड ड्राइव के लिए नए कंट्रोल कंसोल को डिजाइन और विकसित किया गया है।
- उच्चतम सुरक्षा मानकों और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित ब्रेक सिस्टम (सीसीबी 2.0) से इसे लैस किया गया है।
- अधिक संचालन के लिए 6000 लीटर का बड़ा ईंधन टैंक दिया गया है।

घरेलू डिजाइन

ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की तरफ से पहला केप गेज लोकोमोटिव निर्माण है, जो एसी-एसी ट्रैक्शन सिस्टम से विकसित किया गया है। यह 20 टन का वजन और 100 किलोमीटर प्रति/घंटा रफ्तार के लिए सक्षम होने वाला नया डिजाइन है।

एसी-एसी ट्रैक्शन सिस्टम, ट्रैक्शन अल्टरनेटर, ट्रैक्शन मोटर, टर्बो और वॉटर क्लॉजेट को खास तौर पर मोज़ाम्बिक के लिए इस कारखाने के घरेलू डिजाइन सेंटर द्वारा तैयार किया गया है। ■

रक्षा मंत्रालय ने 4,960 एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों की आपूर्ति हेतु बीडीएल के साथ किए हस्ताक्षर

रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने 1,188 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय सेना को 4,960 मिलान-2टी एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीएमएम) की आपूर्ति के लिए रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम (डीपीएसयू)- भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) के साथ एक अनुबंध पर 19 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। इससे सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को और बढ़ावा मिलेगा।

मिलान-2टी 1,850 मीटर की सीमा के साथ एक टेंडम वारहेड एटीजीएम है, जिसे बीडीएल ने एमबीडीए मिसाइल सिस्टम, फ्रांस से लाइसेंस के तहत उत्पादित किया है। इन मिसाइलों को जमीन से और साथ ही वाहन-आधारित लांचर से दागा जा सकता है और आक्रामक एवं रक्षात्मक दोनों कार्यों के लिए एंटी-टैंक रोल में तैनात किया जा सकता है। इन मिसाइलों का इंडक्शन सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को और बढ़ाएगा। इंडक्शन तीन साल में पूरा करने की योजना है। यह परियोजना रक्षा उद्योग के लिए अपनी क्षमता दिखाने का एक बड़ा अवसर है और यह रक्षा क्षेत्र में भी 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक पहल होगी। ■

राष्ट्रवाद को कोई वाद मिटा नहीं सका

दीनदयाल उपाध्याय

भारतीय संस्कृति एवं मर्यादाओं को छोड़कर यदि हमारा जीवन अथवा यहां की राजनीति चली तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इससे न तो हमारा ही हित-साधन होगा, न ही स्वराज्य को साकार कर सकेंगे। भारतीय संस्कृति के नाम पर आज देश में भ्रम एवं अज्ञान व्याप्त है। यह सही है कि संस्कृति शब्द की व्याख्या एक कठिन काम है। इस दृष्टि से अपने देश में तथा बाहर भी प्रयत्न हुए हैं, पर पूर्ण सफलता प्राप्त होती दिखाई नहीं दी है, संस्कृति की व्याख्या आत्मा की व्याख्या के अनुरूप ही कठिन कार्य है। इस कठिनाई के कारण कई विचारक ऐसा अनुभव करते हैं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, यही बात संस्कृति के संबंध में भी लागू की जाती है।

भौगोलिक एवं ऐतिहासिक कारणों से कुछ भिन्नताएं ऐसी हैं, जो मानव समाज के एक अंग में दृष्टिगत होती हैं, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अब भौगोलिक दूरी कम होती जा रही है तथा संपूर्ण मानव-समाज एक-दूसरे के अधिक निकट आता जा रहा है। इससे भिन्न संस्कृतियों जैसी कोई वस्तु न रहकर मानव संस्कृति ही रहेगी। इस स्थिति का विवेचन भी एक कठिन कार्य है आज राष्ट्रों के बीच ऐसे दूरगामी गहरे अंतर हैं, जो जीवन के संपूर्ण दृष्टिकोण से संबंध रखते हैं। आगे यह स्थिति बदल जाएगी, ऐसा दिखाई भी नहीं देता है।

राष्ट्रवाद एक शक्ति है, आंखें बंद करके उसको न मानना अनुचित है। उसी आधार पर संस्कृति जीवन का दृष्टिकोण है, जिसके मूल में सदैव दर्शन रहता है। हमारे यहां इस पर गंभीर रूप से विचार हुआ है

राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रश्न

संपूर्ण मानव-समाज को एक आधार पर खड़े करने के प्रयत्न हुए हैं, परंतु राष्ट्रवाद की भित्ति से टकराकर वे असफल सिद्ध हुए हैं, ईसाइयत का प्रयत्न भी एक ऐसा ही प्रयत्न था। वह राष्ट्र नहीं मानती, संपूर्ण मानव को ईसाइयत के आधार पर एक करना चाहती थी, परंतु राष्ट्रवाद की टक्कर में ईसाइयत पीछे पड़ गई। एक ही मतावलंबी होने के पश्चात् भी आज यूरोप में भिन्न राष्ट्र खड़े हैं। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का जब भी प्रश्न उठा, ईसाइयत गौण हो गई।

इसलाम का प्रयत्न भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसलाम भी राष्ट्र नहीं मानता। संसार के लोगों को इसलाम के आधार पर बांधने के प्रयास हुए हैं, इसलाम एवं गैर-इसलाम यही एक अंतर माना गया, परंतु यह तर्क व्यवहार में चल नहीं पाया। पश्चिम एशिया के अरब देशों में अब राष्ट्रवाद प्रमुख हो गया है। मुसलिम शासक पहले खलीफा के नाम पर शासन करते थे परंतु स्वयं तुर्की ने अपने यहां से खलीफा को निकाल बाहर किया। ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र, सीरिया आदि में आज राष्ट्रवाद ही प्रमुख हो रहा है । इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है, जिसका अरबों से परंपरागत धार्मिक झगड़ा है, परंतु फिर भी तुर्कों ने इसे राजनीतिक मान्यता प्रदान कर दी, राजनीति में उन्होंने धर्म को पीछे छोड़ दिया।

अनेक देशों में जीवन की रचना, विकास, सामाजिक संबंध, साहित्य, राजनीति आदि पर इसलाम का प्रभाव न होकर उनकी परंपराओं का पड़ा है। इंडोनेशिया में इसलाम का प्रभाव होते हुए भी वहां की परंपरा एवं संस्कृति पूर्णतया भिन्न है। पाकिस्तान की जीवन रचना में नारा भले ही इसलाम का लगाया गया हो किंतु वहां परंपरा का प्रभाव पड़ा है। कठमुल्लाओं को यदि छोड़ दिया जाए तो सामान्य समाज एक स्तर पर आ रहा है। प्राचीनकाल में महमूद गजनवी एक पक्का मुसलमान समझा जाता था, वह मूर्ति-भंजक था। सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर का विध्वंस उसी ने किया था, किंतु जब उसने फिरदौसी से अपना इतिहास लिखवाया तो वह इतिहास इसलाम का नहीं बना। उसने रुस्तम और सोहराब के गीत गवाए, जो मुसलमान नहीं थे। पाकिस्तान की सरकार ने भी पाकिस्तान के 5000 वर्ष नामक एक पुस्तक छपाई है, इसमें मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा का इतिहास लिखा गया है, राजा दाहिर की वीरता के गुणगान गाए गए।

राजा पुरु के पराक्रम का भी वर्णन है, विदेशियों के आक्रमण का भी चित्रण है। यह हो सकता है कि इसमें भाषा के प्रयोग में अंतर रहा हो, परंतु भाव परंपरागत है। पाकिस्तान बनने के पूर्व तक

बंगाल में उर्दू भाषा के लिए आंदोलन किया गया, परंतु अंत में उन्होंने अपनी बंगला भाषा को ही स्वीकार किया है। पुरातन-परंपरा प्रमुख नहीं, ऐसा सोचना अस्वाभाविक होगा।

कम्युनिज्म रूसी राष्ट्रवाद का नारा

आज के समय में साम्यवाद के नाम पर ऐसा प्रयत्न चला है। वास्तव में तो इस व्यवस्था को साम्यवाद नाम देना ही उचित नहीं। कम्युनिज्म राष्ट्रवाद को नहीं मानता, शोषक एवं शोषित के आधार पर उन्होंने समाज का वर्गीकरण करना चाहा, परंतु वह चल नहीं पाया। स्वयं लेनिन को अपने देश के लिए मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या अपने अनुरूप करनी पड़ी। आज कम्युनिज्म रूसी राष्ट्रवाद का हथियार बन गया है। वह दूसरे देशों के राष्ट्रवाद से टकराया है। चीन एवं रूस के मनमुटाव का कारण राष्ट्रवाद है। युगोस्लाविया का पृथकीकरण, हंगरी एवं पोलैंड के विद्रोह पृथक् राष्ट्रवाद की झलक हैं, आज जो मेल है, वह अधीनता के कारण है।

संस्कृति जीवन का एक दार्शनिक दृष्टिकोण है

राष्ट्रवाद एक शक्ति है, आंखें बंद करके उसको न मानना अनुचित है। उसी आधार पर संस्कृति जीवन का दृष्टिकोण है, जिसके मूल में सदैव दर्शन रहता है। हमारे यहां इस पर गंभीर रूप से विचार हुआ है। सत्य क्या है, इसकी खोज में हमारे लोग लगे रहे हैं। हमने जीवन में मोटे रूप से चार सत्ताएं मानी हैं-1. व्यष्टि (प्राणी), 2. सृष्टि (प्रकृति), 3. समष्टि (समाज), 4. परमेष्टि (ईश्वर-ब्रह्म)। जहां तक चौथी सत्ता का प्रश्न है, इस संबंध में मतभेद रहे हैं। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, समष्टि का अर्थ समाज अधिक सरल है।

मनुष्य समाज के रूप में एक साथ कई स्थानों पर पैदा हुआ। प्रत्येक समाज अपनी कुछ मूल प्रकृति लेकर उत्पन्न हुआ। वनस्पति की भी एक मूल प्रकृति होती है। आम की एक मूल प्रकृति है। बीज, खाद, वायु, पानी के कारण अंतर आता रहता है, परंतु मूल एक ही रहता है। समाज की भी एक मूल प्रकृति है। इस मूल प्रकृति को ही 'चिति' कहते हैं

समाज का अर्थ भी आज कई रूप में लिया जाता है, दस लोग जहां एकत्र होते हैं। उसे भी समाज कहते हैं तथा संपूर्ण मानव समाज को भी समाज की संज्ञा दी जाती है। मानव की उत्पत्ति के संबंध में भी विचार हुआ है। हम डार्विन के सिद्धांत को नहीं मानते, जहां कि बंदर से सुधारकर मानव का निर्माण हुआ। हम यह भी नहीं मानते कि सबसे पहले आदम और हव्वा उत्पन्न हुए जिनकी कि संतान मनुष्य हैं। मनुष्य को भी एक अमैथुनिक सृष्टि है। मनुष्य समाज के रूप में एक साथ कई स्थानों पर पैदा हुआ। प्रत्येक समाज अपनी कुछ मूल प्रकृति लेकर उत्पन्न हुआ। वनस्पति की भी एक मूल प्रकृति होती है। आम की एक मूल प्रकृति है। बीज, खाद, वायु, पानी के कारण अंतर आता रहता है, परंतु मूल एक ही रहता है। समाज की भी एक मूल प्रकृति है। इस मूल प्रकृति को ही 'चिति' कहते हैं। हम सब एक हैं, यह क्यों कर लगता है, क्योंकि हमारी चिति एक है, चिति हो संस्कारयुक्त होकर संस्कृति बन जाती है, आज जो सांस्कृतिक भिन्नता दिखाई देती है, उसका कारण है कि मूल समाजों की चिति प्रकृति भिन्न थी। चिति तब समझ में आती है, जब परमानंद एवं परमवैभव की अनुभूति का आधार होता है, प्रेय एवं श्रेय का विवेचन किया जाता है, जीवन का परम सुख जहां मिलता है, वह समाज की चिति है। ■

(क्रमशः....)

-पाञ्चजन्य, सितंबर 3, 1962

संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने उपहार में दो लाख कोविड-19 टीके देने के लिए भारत का जताया आभार

संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक अभियानों के प्रमुख सहित उसके शीर्ष अधिकारियों ने शांति सैनिकों के लिए कोविड-19 टीकों की 2,00,000 खुराकें उपहार में देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह दान शांति सैनिकों को अपने जीवन-रक्षक कार्य को सुरक्षित तरीके से जारी रखने में सक्षम करेगा। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के लिए भारत द्वारा उपहार के रूप में दी गई कोविड-19 टीकों की 2,00,000 खुराकें 27 मार्च की सुबह मुंबई से भेजी गईं, जो डेनमार्क के कोपेनहेगन पहुंचेंगी। फिर उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सभी शांति रक्षा अभियानों के लिए वितरित किया जाएगा। शांति रक्षा अभियानों के लिए अवर महासचिव जीन-पियरे लैक्रोइक्स और संचालन सहायता के लिए अवर महासचिव अतुल खरे ने 26 मार्च को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए टीके की खुराक देने के लिए भारत की सराहना की। ■

नहीं रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री दिलीप गांधी का 17 मार्च को दिल्ली में निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे। श्री दिलीप गांधी 1999 में अहमदनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार सांसद चुने गए। वह अहमदनगर से तीन बार सांसद रहे। वे श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्ववाली राजग सरकार में केंद्रीय जहाजरानी राज्यमंत्री थे।

श्री गांधी के निधन पर श्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि पूर्व सांसद और मंत्री दिलीप गांधी जी के निधन की खबर से दुःख हुआ। सामुदायिक सेवा में उनके समृद्ध योगदान और गरीबों की मदद करने के लिए उन्हें याद किया जाएगा। उन्होंने

महाराष्ट्र में भाजपा को मजबूत करने के लिए अनेक प्रयास किए। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने श्री गांधी के निधन पर ट्वीट कर कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता श्री दिलीप गांधी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। उनका सम्पूर्ण जीवन जनसेवा और संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु समर्पित रहा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति व दुःख की इस घड़ी में परिजनों को संबल प्रदान करें।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने श्री गांधी के निधन पर ट्वीट कर कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री व पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दिलीप गांधी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। दिलीप जी का पूरा जीवन जनता की सेवा व संगठन कार्यों में समर्पित रहा। ईश्वर उनके परिजनों को यह असहनीय पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करे। ■

भाजपा सांसद राम स्वरूप शर्मा का आकस्मिक निधन

हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री राम स्वरूप शर्मा का 17 मार्च को नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर आकस्मिक निधन हो गया। वे 62 वर्ष के थे। श्री शर्मा दो बार सांसद रहे। वे हिमाचल प्रदेश के मंडी लोक सभा क्षेत्र से 2014 व 2019 में सांसद चुने गए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि श्री राम स्वरूप शर्मा एक समर्पित नेता थे, जो हमेशा लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समाज की भलाई के लिए अथक परिश्रम किया। उनके असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन से पीड़ा पहुंची है। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार और समर्थकों के साथ हैं।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने श्री शर्मा के निधन पर ट्वीट कर कहा कि श्री राम स्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन के समाचार से मन अत्यंत व्यथित है। मैं शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करता हूं।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि हिमाचल श्री राम स्वरूप शर्मा की मृत्यु के समाचार से मुझे बहुत दुःख हुआ है। उनका पूरा जीवन देश और समाज के प्रति समर्पित रहा। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को नीचे तक मजबूत बनाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि श्री राम स्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन से अत्यंत व्यथित हूं। मैं दुःख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं व दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ■

कमल संदेश परिवार की ओर से स्व. दिलीप गांधी एवं स्व. राम स्वरूप शर्मा के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि।

'बीज से लेकर बाजार तक किसान की हर दिक्कत को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास'

यूं तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दिनचर्या काफी व्यस्त रहती है, मगर कम ही लोगों को यह पता होगा कि उन्हें जब भी मौका मिलता है वह अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर लोगों की चिट्ठियों और उनके संदेशों का जवाब देने से चूकते नहीं हैं। ऐसा ही एक पत्र मिला है नैनीताल, उत्तराखण्ड के श्री खीमानंद को, जिन्होंने नरेन्द्र मोदी ऐप (नमो ऐप) के जरिए पीएम को संदेश भेजकर 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के 5 सफल वर्ष पूरे होने और सरकार के अन्य प्रयासों के लिए बधाई दी थी। अब प्रधानमंत्री ने श्री खीमानंद को पत्र लिखकर उन्हें उनके बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पत्र में लिखा कि कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों पर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए आपका आभार। ऐसे आत्मीय सन्देश मुझे देश की सेवा में जी-जान से जुटे रहने की नई ऊर्जा देते हैं।

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' की सफलता का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम की अनिश्चितता से जुड़े जोखिम को कम कर मेहनती किसान भाई-बहनों के आर्थिक हितों की रक्षा करने में लगातार अहम भूमिका निभा रही है। किसान हितैषी बीमा योजना का लाभ आज करोड़ों किसान ले रहे हैं।

कृषि और किसान कल्याण के प्रति संकल्पित सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे पत्र में लिखा कि पिछले पांच वर्षों में व्यापक कवरेज और पारदर्शी दावा निस्तारण प्रक्रिया के माध्यम से यह योजना किसान कल्याण को समर्पित हमारे संकल्पित प्रयासों और पक्के इरादों की एक महत्वपूर्ण मिसाल बनकर उभरी है।

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' मौसम की अनिश्चितता से जुड़े जोखिम को कम कर मेहनती किसान भाई-बहनों के आर्थिक हितों की रक्षा करने में लगातार अहम भूमिका निभा रही है

श्री मोदी ने कहा कि आज बीज से लेकर बाजार तक किसान भाई-बहनों की हर छोटी-बड़ी दिक्कतों को दूर करने और अन्नदाता की समृद्धि और कृषि की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

इसके साथ ही उन्होंने देश की प्रगति में देशवासियों के योगदान और उनकी भूमिका की सराहना करते हुए लिखा कि सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के दृष्टिकोण के साथ आज देश एक सशक्त, समृद्ध और 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण की ओर तेजी से अग्रसर है। समस्त देशवासियों के विश्वास से ऊर्जित देश राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकनिष्ठ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश को विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे प्रयास आगे और तेज होंगे।

इससे पहले श्री खीमानंद ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को अपने संदेश में फसल बीमा योजना के 5 सफल वर्ष पूरे होने पर बधाई दी थी। साथ ही, श्री खीमानंद ने कहा था प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जरिए नागरिकों की उन्नति और राष्ट्र की प्रगति के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ■

भारत कभी अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूलेगा: नरेन्द्र मोदी

आजादी अमृत महोत्सव यानी स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत है। इसका अर्थ- स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की प्रेरणाओं का अमृत; नए विचारों और संकल्पों का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पदयात्रा (फ्रीडम मार्च) को झंडी दिखाई तथा 'आजादी का अमृत महोत्सव' इंडिया@75 के पूर्वावलोकन कार्यकलापों का उद्घाटन किया। उन्होंने इंडिया@75 समारोहों के लिए अन्य विभिन्न सांस्कृतिक और डिजिटल पहलों को भी लांच किया। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी भी उपस्थित थे।

आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक शृंखला है। यह महोत्सव जनभागीदारी की भावना में एक जन-उत्सव के रूप में मनाया जाएगा।

साबरमती आश्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने 15 अगस्त, 2022 से 75 सप्ताह पूर्व 'आजादी का अमृत महोत्सव' आरंभ किए जाने की चर्चा की जो 15 अगस्त, 2023 तक चलेगा। उन्होंने महात्मा गांधी और महान व्यक्तित्वों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी।

श्री मोदी ने पांच स्तंभों अर्थात स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां, 75 पर कार्रवाइयां तथा 75 पर संकल्प को प्रेरणा मानते हुए सपनों और दायित्वों को बनाए रखने तथा आगे बढ़ने के मार्गदर्शी बल के रूप में दोहराया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि आजादी अमृत महोत्सव का अर्थ स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत है। इसका अर्थ हुआ स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की प्रेरणाओं का अमृत; नए विचारों और संकल्पों का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत।

नमक के प्रतीक की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केवल लागत के आधार पर नमक का मूल्य कभी भी नहीं आंका गया। भारतीयों के लिए नमक का अर्थ ईमानदारी, भरोसा, वफादारी, श्रम, समानता और आत्मनिर्भरता है।

उन्होंने कहा कि उस समय नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। ब्रिटिश सरकार ने भारत के मूल्यों के साथ-साथ इस आत्मनिर्भरता को भी क्षति पहुंचाई। भारत के लोगों को इंग्लैंड से आने वाले नमक पर निर्भर रहना पड़ता था। श्री मोदी ने कहा कि गांधी जी ने देश के इस पुराने दर्द को समझा, लोगों की धड़कन को समझा तथा उसे एक आंदोलन में तब्दील कर दिया।

श्री मोदी ने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध, विदेश से महात्मा गांधी के लौटने, सत्याग्रह की शक्ति का राष्ट्र को स्मरण कराने, लोकमान्य तिलक द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का दिल्ली मार्च तथा दिल्ली चलो के नारे जैसे स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण क्षणों को याद किया।

उन्होंने यह भी कहा कि स्वाधीनता आंदोलन के इस अलख को निरंतर जगाए रखने का काम प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक दिशा में देश के कोने-कोने में हमारे आचार्यों, संतों तथा शिक्षकों द्वारा किया गया था।

श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता आंदोलन के लिए मंच तैयार किया। चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, श्रीमंत शंकर देव ने एक राष्ट्रव्यापी स्वतंत्रता संग्राम की आधारशिला का निर्माण किया। इसी प्रकार, देश के सभी क्षेत्रों के संतों ने राष्ट्र की चेतना और स्वाधीनता संग्राम में योगदान दिया। देश भर के ऐसे कई दलित, आदिवासी, महिलाएं और युवक थे, जिन्होंने अनगिनत कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने तमिलनाडु के 32 वर्षीय कोडी कठा कुमारन जैसे अज्ञात नायकों की कुर्बानियों को याद किया, जिसने ब्रिटिश सेना द्वारा सर में गोली लगने के बावजूद देश के झंडे को जमीन पर नहीं गिरने दिया। तमिलनाडु की वेलु नचियार पहली महारानी थी, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ीं।

श्री मोदी ने टिप्पणी की कि हमारे देश के जनजातीय समाज ने विदेशी शासन को झुकाने के लिए निरंतर बहादुरी और हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी। झारखंड में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को चुनौती दी तथा मुर्मु बंधुओं ने संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया। ओडिशा में चकरा बिसोई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ीं तथा लक्ष्मण नायक ने गांधीवादी सिद्धांतों के जरिए जागरूकता फैलाई। उन्होंने आंध प्रदेश में मन्याम विरुडु अलुरी सिराराम राजू, जिसने राम्पा आंदोलन का नेतृत्व किया तथा पसाल्था खुंगचेरा जिसने मिजोरम की पहाड़ियों में अंग्रेजों का सामना किया, जैसे अन्य अज्ञात जनजातीय नायकों का भी नाम लिया, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने गोमधर कोन्वार, लक्षित बोरफुकन तथा सेरात सिंह जैसे असम तथा पूर्वोत्तर के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि देश हमेशा गुजरात के जम्बुघोडा में नायक जनजातीयों के बलिदान तथा मानगाध में सैंकड़ों आदिवासियों के नरसंहार को याद रखेगा।

श्री मोदी ने कहा कि देश प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक क्षेत्र में इसके इतिहास को संरक्षित करने के लिए पिछले छह वर्षों से सजग प्रयास करता रहा है। दांडी यात्रा के साथ जुड़े स्थल का पुनरुत्थान दो वर्ष पहले किया गया। उस स्थान का भी पुनरुत्थान किया जा रहा है, जहां देश की प्रथम स्वतंत्र सरकार के निर्माण के बाद नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराया था। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के साथ जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है, जालियांवाला बाग में स्मारक तथा पैका आंदोलन के स्मारक का भी विकास किया जा रहा है।

हमने भारत तथा विदेश दोनों ही जगहों पर अपनी कड़ी मेहनत के साथ खुद को साबित किया है। हम अपने संस्थान और लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व करते हैं

श्री मोदी ने कहा कि हमने भारत तथा विदेश दोनों ही जगहों पर अपनी कड़ी मेहनत के साथ खुद को साबित किया है। हम अपने संस्थान और लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी भारत अभी भी लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने युवाओं और विद्वानों से हमारे स्वाधीनता सेनानियों के इतिहास के दस्तावेजीकरण के द्वारा देश के प्रयासों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे स्वतंत्रता आंदोलन की उपलब्धियों को विश्व के सामने प्रदर्शित करने का अनुरोध किया।

श्री मोदी ने कला, साहित्य, थियेटर की दुनिया, फिल्म उद्योग तथा डिजिटल मनोरंजन से जुड़े लोगों से उन अनूठी कहानियों, जो हमारे अतीत में बिखरी हुई हैं, की खोज करने और उनमें नया जीवन डालने का आग्रह किया। ■

तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

श्री तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च, 2021 को देहरादून में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

श्री तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल से भाजपा के लोकसभा सांसद हैं। इससे पहले वह 2013 और 2015 के बीच उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष तथा 2012 से 2017 तक चौबट्टाखाल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भी रहे। उन्हें 10 मार्च, 2021 को उत्तराखंड भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। जिसके बाद उनको उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलायी गयी।

देहरादून के राजभवन में राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य द्वारा श्री रावत को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद श्री तीरथ सिंह रावत को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बधाई दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, "श्री तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। वह प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव के धनी हैं। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा।"

वहीं एक ट्वीट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, "तीरथ सिंह रावत जी को देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य विकास के नये मापदंड स्थापित करेगा और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचेगा।"

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के नये मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का सीएम बनने पर बधाई। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में राज्य को नई ऊर्जा मिलेगी और देवभूमि में प्रगति और जन कल्याण के नए मानक स्थापित होंगे।

उत्तराखंड़ कैबिनेट का विस्तार; 11 मंत्रियों ने ली शपथ

उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के दो दिन बाद श्री तीरथ सिंह रावत ने 12 मार्च, 2021 को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए आठ कैबिनेट मंत्री और तीन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को शपथ दिलायी।

राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने देहरादून में राजभवन में एक समारोह में मंत्रियों को शपथ दिलाई।

इस मंत्रिमंडल विस्तार में सर्वश्री सतपाल महाराज, बंसीधर भगत, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चौपाल, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, गणेश जोशी और सुबोध उनियाल को कैबिनेट मंत्री और रेखा आर्य, धन सिंह रावत और स्वामी यतिस्वरानंद को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के तौर पर शपथ दिलायी गयी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद श्री रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और अन्य लोगों का आभार व्यक्त किया और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले एक सामान्य कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी दिये जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां तक पहुंचूंगा, मैं लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करूंगा और पिछले 4 वर्षों में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा।" ■

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा का शुभारंभ

पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ गए हैं: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 16 मार्च को पश्चिम बंगाल के कोतुलपुर निर्वाचन क्षेत्र से बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्रा का शुभारंभ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और पश्चिम बंगाल प्रदेश प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसद सदस्य श्री सौमित्र खान की उपस्थिति में किया गया।

श्री नड्डा ने अपने उद्घाटन भाषण में वर्तमान राज्य सरकार की निंदा की, जिसके तहत अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार पिछले 10 वर्षों में खतरनाक रूप से बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों के 100 से अधिक निर्दोष लोगों की पिछले 2 वर्षों में हत्या कर दी गई है और वहीं राज्य में 68% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। उन्होंने आगे कहा कि अम्फान चक्रवात राहत के दौरान दिए गए केंद्र सरकार के धन का गंभीर कुप्रबंधन हुआ है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2011 में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार 59% था, जो 2019 में 119% तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि यह सरकार अनुसूचित जाति विरोधी सरकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय सुनिश्चित करने में विफल रही है और उसने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया है जिससे पश्चिम बंगाल की छवि धूमिल हो गई है। मौजूदा तृणमूल सरकार केवल तुष्टिकरण की राजनीति में विश्वास रखती है, लोगों के विकास में नहीं। पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों, किसानों के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जैसे– स्वच्छ भारत योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत आदि। किन्तु मुझे यह जानकर पीड़ा होती है कि बंगाल के गरीबों को इन सभी योजनाओं से वंचित रखा तृणमूल सरकार ने। हमारी सरकार बनते ही महीसा और तेली जातियों को आरक्षण का लाभ दिलवाने के लिए तुरंत आयोग का गठन किया जाएगा। भीमराव अंबेडकर के सम्मान में शुरू की गई यात्रा 189 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। श्री नड्डा ने भीमराव अंबेडकर को सम्मानित नहीं करने के लिए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबासाहेब को वह सम्मान नहीं दिया गया, जो उन्हें जीवित रहते हुए मिलना चाहिए था, लेकिन भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि उनका सपना साकार हो। ■

सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत के लिए मिलकर काम करेंगे: नरेन्द्र मोदी

शिखर सम्मेलन में समकालीन चुनौतियों जैसे लचीली सप्लाई चेन व्यवस्था, नई उभरती महत्वपूर्ण टेक्नोलोजी, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मार्च, 2021 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री श्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जोसेफ आर. बाइडेन के साथ क्वाड्रीलैटरल समूह के नेताओं के पहले वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया।

सभी नेताओं ने साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के क्षेत्रों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। इस शिखर सम्मेलन में समकालीन चुनौतियों जैसे लचीली सप्लाई चेन व्यवस्था, नई उभरती महत्वपूर्ण टेक्नोलोजी, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई।

कोरोना महामारी को समाप्त करने में मदद करने के लिए सभी नेताओं ने सुरक्षित, सुलभ और प्रभावी टीकों के उत्पादन में विस्तार और तेजी लाने पर जोर दिया।

वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर हमारी प्रतिबद्धता के लिए एकजुट हैं।

क्वाड अब विकसित हो चुका है। यह अब क्षेत्र में स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा

श्री मोदी ने कहा कि आज हमारे एजेंडे में टीका, जलवायु परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जो वैश्विक भलाई के लिए क्वाड को एक ताकत बनाते हैं। मैं इस सकारात्मक नजरिये को भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम' के प्राचीन दर्शन के विस्तार के रूप में देखता हूं, जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। उन्होंने कहा कि हम अपने साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने और एक सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत को बढ़ावा देने के लिए पहले से कहीं अधिक साथ मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आज का शिखर सम्मेलन बताता है कि क्वाड अब विकसित हो चुका है। यह अब क्षेत्र में स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा। ■

'आयुर्वेदिक उत्पादों की वैश्विक मांग निरंतर बढ़ रही है'

आयुर्वेदिक और पारंपरिक चिकित्सा के प्रति रूझान निरंतर बढ़ रहा है। विश्व इसका साक्षी है कि आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रकार की औषधियां स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मार्च को वर्चुअल माध्यम से चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद के प्रति बढ़ती वैश्विक रुचि का उल्लेख करते हुए सम्पूर्ण दुनिया में आयुर्वेद पर कार्य कर रहे सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की।

कोविड-19 महामारी के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति आयुर्वेद और पारंपरिक औषधियों को वैश्विक स्तर पर और भी लोकप्रिय बनाने का एक उपयुक्त समय है। आयुर्वेदिक और पारंपरिक चिकित्सा के प्रति रूझान निरंतर बढ़ रहा है। विश्व इसका साक्षी है कि आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रकार की औषधियां स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं।

श्री मोदी ने कहा कि लोग आयुर्वेद के लाभ और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में इसकी भूमिका का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं। भारत में स्वास्थ्य पर्यटन क्षमता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि रोग का निदान, तत्पश्चात स्वास्थ्य का सिद्धांत ही स्वास्थ्य पर्यटन का मूल है। इसलिए स्वास्थ्य पर्यटन का सबसे मजबूत स्तंभ आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा है।

उन्होंने उपस्थित जनसमूह से मानसिक तनाव को कम करने और उपचार के लिए भारत की शाश्वत संस्कृति से लाभ लेने आह्वान किया। श्री मोदी ने आमंत्रण देते हुए कहा कि आप चाहे अपने शरीर का इलाज कराना चाहते हैं या अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो भारत आएं।

श्री मोदी ने आयुर्वेद की लोकप्रियता और आधुनिक चिकित्सा के साथ पारंपरिक चिकित्सा के संयोजन के अवसरों का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। आयुर्वेद उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करने वाले युवाओं की स्थितियों और साक्ष्य-आधारित चिकित्सा विज्ञान के साथ आयुर्वेद को एकीकृत करने के लिए बढ़ती जागरूकता का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने शिक्षाविदों से आयुर्वेद और चिकित्सा के पारंपरिक रूपों पर शोध को और अधिक गहन करने का आह्वान किया।

सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद जगत को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को लागत प्रभावी आयुष सेवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। यह शैक्षिक प्रणालियों को मजबूत करने और आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण के प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाने और कच्चे माल की स्थायी उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण उपायों पर भी कार्य कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य भारतीय प्रणालियों के विषय में हमारी नीति पहले से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014-2023 के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने भारत में वैश्विक पारंपरिक औषधि केन्द्र की स्थापना की भी घोषणा की है।

श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित करने का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज के लाभों के विषय में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। ■

भाजपा संसदीय दल की बैठक

'महामारी और आपदाओं के बावजूद मजबूत भारत'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 मार्च, 2021 को भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी, भारत-चीन सीमा तनाव, चक्रवात, भूकंप जैसी परिस्थितियों के बावजूद देश मजबूत हुआ है और दुनिया ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक कृषि कानूनों पर भी बात की।

बैठक के दौरान श्री मोदी ने पंचायत चुनावों में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का हवाला दिया, जो जनता के बीच इनकी स्वीकार्यता की ओर इशारा करते हैं और यही कारण है कि हम इन कानूनों के साथ खड़े हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी के लोकसभा क्षेत्र पाली में संपन्न पंचायत चुनावों का हवाला दिया, जिसमें भाजपा ने 90 प्रतिशत से अधिक सीटें जीती थीं, जहां चुनाव कृषि कानूनों के खिलाफ होने वाले विरोध-प्रदर्शनों के बीच हुए थे।

कोरोना महामारी के अपने अनुभवों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने सांसदों को यह भी बताया कि उस अवधि के दौरान देश न केवल वायरस की चुनौती का सामना कर रहा था, बल्कि अन्य मोर्चों जैसे भारत-चीन सीमा पर तनाव, चक्रवात, भूकंप और फिर टिड्डी दल का हमला जैसे मुद्दों पर भी जूझ रहा था, लेकिन इन सभी बाधाओं के बावजूद भारत मजबूत हुआ और पूरी दुनिया को अपनी क्षमता का एहसास करवाने में कामयाब हुआ।

कोविड-19 महामारी, भारत-चीन सीमा तनाव, चक्रवात, भूकंप जैसी परिस्थितियों के बावजूद देश मजबूत हुआ है और दुनिया ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है

श्री नरेन्द्र मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि वे एक राज्य के मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के रूप में दो दशकों से अधिक समय से सार्वजनिक जीवन में बिना किसी अवकाश के कार्य कर रहे हैं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक के बाद मीडिया को इसकी जानकारी दी।

प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने भी बैठक को संबोधित किया। श्री जयशंकर ने बताया कि भारत का कद दुनिया भर में अपनी चिकित्सा कूटनीति के कारण बढ़ा है– इस क्रम में भारत ने पहले एंटीबायोटिक्स और परीक्षण किट प्रदान किये और बाद में वैक्सीन कूटनीति से भारत की छवि को बढ़ावा मिला है।

केंद्रीय बजट पर प्रस्तुति देते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि महामारी के आर्थिक प्रभाव के बावजूद सरकार ने जनता पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया और सभी के लिए एक व्यापक बजट लेकर आयी है। ■

भारत और फिनलैंड ने बहुलवाद व कानून आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर जताई मजबूत प्रतिबद्धता

दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध लोकतंत्र के साझा मूल्यों, कानून के शासन, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सम्मान पर आधारित हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और फिनलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री एच.ई. सुश्री सना मारिन ने 16 मार्च को एक वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर दोनों देशों ने द्विपक्षीय मुद्दों के साथ-साथ आपसी हित के अन्य क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और फिनलैंड के बीच घनिष्ठ संबंध लोकतंत्र के साझा मूल्यों, कानून के शासन, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सम्मान पर आधारित हैं।

उन्होंने बहुलवाद, कानून आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काम करने की अपनी मजबूत प्रतिबद्धता की फिर से दोहराया।

नेताओं ने दोनों देशों के बीच चल रहे द्विपक्षीय कार्यों की समीक्षा की और इस बात की उम्मीद जताई कि दोनों देश व्यापार और निवेश, इनोवेशन, शिक्षा, नई तकनीकी जैसे- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5 जी/6जी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में संबंधों का और विस्तार करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वच्छ और ग्रीन प्रौद्योगिकी में फिनलैंड की अग्रणी भूमिका की सराहना की और फिनलैंड की कंपनियों को टिकाऊ विकास की दिशा में भारत के चलाए जा रहे अभियान में सहयोग बढ़ाने का आह्वान भी किया। इस संदर्भ में उन्होंने नवीकरणीय और जैव-ऊर्जा, टिकाऊ तकनीकी, शिक्षा, दवा और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया।

इस मौके पर दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी, आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग, विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र में सुधार जैसे मुद्दे शामिल हैं। दोनों पक्षों ने अफ्रीका में विकास संबंधी गतिविधियों में सहयोग करने के लिए भारत और फिनलैंड की भागीदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा की।

श्री मोदी ने फिनलैंड को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा प्रतिरोधक आधारभूत संरचना गठबंधन (सीडीआरआई) में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

दोनों नेताओं ने कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण अभियान पर भी चर्चा की और सभी देशों में टीकों के लिए तत्काल और सस्ती पहुंच के लिए वैश्विक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया।

दोनों नेताओं ने पोर्टो में भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक और भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान एक बार फिर से मिलने की प्रतिबद्धता जताई। ■

भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार

भारत के पास इस समय दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। इस मामले में भारत ने रूस को पीछे छोड़ दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हालिया विज्ञप्ति के अनुसार 5 मार्च को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 580.3 अरब डॉलर था, जबकि रूस का विदेशी मुद्रा भंडार 580.1 अरब डॉलर रहा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है, जबकि जापान दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है।

गौरतलब है कि भारत और रूस के विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले कई महीनों से वृद्धि जारी है। भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वह 18 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। भारतीय शेयर बाजारों में एफआईआई द्वारा भारी निवेश और एफडीआई के जरिये निवेश में वृद्धि से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड उछाल आया है।

साथ ही, आरबीआई की एक हालिया रिपोर्ट में विदेशी मुद्रा भंडार को और मजबूत करने की सिफारिश की गई है। आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के अनुसार उभरते बाजार को देखते हुए केंद्रीय बैंकों को किसी भी बाहरी झटके से रोकने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ाने की जरूरत है। ■

'टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट' की रणनीति पर गंभीर होने की जरूरत: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री ने देश में टीकाकरण की लगातार बढ़ रही गति और एक ही दिन 30 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किए जाने की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर 17 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। मुख्यमंत्रियों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने पूरे देश में टीकाकरण अभियान के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही, टीकाकरण के दायरे को बढ़ाने के लिए कई सारे सुझाव भी दिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टीकाकरण अभियान पहुंच सके।

इस दौरान आम जनता में कोविड-19 से बचाव के लिए उचित व्यवहार को बनाए रखने की चुनौती पर भी चर्चा की गई। खास तौर से ऐसी स्थिति में जब हाल ही में कुछ राज्यों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई। राज्य के मुख्यमंत्रियों ने स्थिति को अधिक सतर्कता और निगरानी से हल करने की जरूरत पर भी सहमति जताई।

बातचीत के दौरान गृह मंत्री ने उन जिलों को सूची भी प्रस्तुत की, जहां पर मुख्यमंत्रियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। साथ ही, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने देश में मौजूदा कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक प्रस्तुति भी दी।

मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोविड-19 से संक्रमित 96 फीसदी लोग ठीक हो चुके हैं और इसकी वजह से भारत दुनिया

में सबसे कम मृत्यु दर वाला देश रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे मामलों पर चिंता जताई।

श्री मोदी ने कहा कि देश के 70 जिलों में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना के मामलों में 150 फीसदी की दर से बढ़ोतरी हुई है।

भारत में कोविड-19 से संक्रमित 96 फीसदी लोग ठीक हो चुके हैं और इसकी वजह से भारत दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर वाला देश रहा है

उन्होंने आग्रह किया कि दोबारा तेजी से बढ़ने वाले संक्रमण को तुरंत रोकने की जरूरत है, नहीं तो कोरोना की दूसरी लहर को रोकना मुश्किल होगा और ऐसा नहीं कर पाने पर पूरे देश में कोरोना की विस्फोटक स्थिति होने का डर है।

श्री मोदी ने माइक्रो संक्रमित क्षेत्र के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा इस समय 'टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट' की रणनीति पर गंभीर होने की जरूरत है। जैसाकि हम पिछले एक साल से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर परीक्षण दर को 70 प्रतिशत से ऊपर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और यूपी जैसे राज्यों में आरटी-पीसीआर परीक्षणों पर ज्यादा जोर देने को कहा। यह राज्य रैपिड एंटीजन परीक्षणों पर अधिक बल दे रहे हैं।

श्री मोदी ने छोटे शहरों में परीक्षण बढ़ाने, 'रेफरल सिस्टम' और 'एम्बुलेंस नेटवर्क' पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब पूरा देश यात्रा के लिए खुल चुका है और यात्रा करने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।

श्री मोदी ने आपस में जानकारी साझा करने के लिए एक नए तंत्र की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा इसी तरह विदेश से आने वाले यात्रियों के संपर्कों की निगरानी के लिए एसओपी का पालन कराने की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।

श्री मोदी ने कहा कि हमें कोरोना वायरस के म्यूटेंट की पहचान करने और उसके प्रभावों का आकलन करने की आवश्यकता है। उन्होंने देश में टीकाकरण की लगातार बढ़ रही गति और एक ही दिन 30 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किए जाने की भी सराहना की। ■

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण 80 से ज्यादा दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने मरीजों को पेटेंट समाप्त होने का लाभ देने के लिए पेटेंट रहित मधुमेह रोधी दवाओं सहित 81 दवाओं का मूल्य निर्धारित कर दिया है।

एनपीपीए ने मेसर्स वॉकहार्ट की 'इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन, 200 आईयू/एमएल' और '70 प्रतिशत आइसोफेन इंसुलिन ह्यूमन सस्पेंशन + 30 प्रतिशत इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन 200 आईयू/एमएल' का खुदरा मूल्य 106.65 रुपये प्रति एमएल (जीएसटी को छोड़कर) और मेसर्स टॉरंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की 'प्रासुग्रेल हाइड्रोक्लोराइड 10 एमजी (फिल्म कोटेड) + एस्पिरिन 75 एमजी (एंट्रिक कोटेड) कैप्सूल' की कीमत 20.16 रुपये प्रति कैप्सूल (जीएसटी को छोड़कर) तय कर दी हैं। ये नई कीमतें 17 मार्च, 2021 से लागू हो गई हैं।

दोनों दवाएं क्रमशः 132.50 रुपये प्रति एमएल और 27.26 रुपये प्रति कैप्सूल की एमआरपी पर बिक रही थीं। इस मूल्य नियंत्रण के साथ एनपीपीए ने जनता को उचित कीमत पर दवाओं की उपलब्धता का फिर से भरोसा दिलाया है।

एनपीपीए ने स्वदेशी स्तर पर शोध एवं विकास के माध्यम से विकसित नई दवा आपूर्ति व्यवस्था के क्रम में 'औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 के पैरा 32 के अंतर्गत संबंधित कंपनियों को उक्त उल्लिखित फॉर्म्यूलेशंस के लिए' पांच साल की अवधि के लिए कीमत तय करने की छूट दी थी। छूट की अवधि के दौरान मूल्य नियंत्रण लागू नहीं था।

10 मार्च, 2021 को हुई बैठक में एनपीपीए ने छूट की अवधि बीतने के साथ डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के तहत इन फॉर्म्यूलेशन की कीमत नियंत्रित करने का फैसला किया। इसके परिणामस्वरूप 'इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन 200 आईयू/एमएल' और '70 प्रतिशत आइसोफेन इंसुलिन ह्यूमन सस्पेंशन + 30 प्रतिशत इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन 200 आईयू/एमएल' की कीमत मौजूदा मूल्य की तुलना में काफी कम हो गई है। अब ये दवाएं जनता के लिए ज्यादा किफायती हो गई हैं।

एनपीपीए ने 10 मार्च, 2021 को हुई बैठक में पेटेंट रहित मधुमेह रोधी दवा सहित मौजूद विनिर्माताओं द्वारा लॉन्च की जाने वाली 76 नई दवाओं की खुदरा कीमत भी निर्धारित कर दी है, जिससे मरीजों को पेटेंट समाप्त होने का लाभ पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा, एनपीपीए ने एक संक्रमण रोधी फॉर्म्यूलेशन पोविडोन आयोडीन 7.5 प्रतिशत स्क्रब और थॉयराइड से संबंधित बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली लेवो-थायरॉक्सिन 37.5 एमजी टैबलेट नाम के दो अनुसूचित फॉर्म्यूलेशन का अधिकतम मूल्य तय कर दिया है, जिससे उनकी वर्तमान कीमत में खासी कमी आ गई है।

अनुसूचित फॉर्म्यूलेशन के वर्तमान अधिकतम मूल्य में संशोधन थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित है, जिसे प्राधिकरण द्वारा ही मंजूरी दी गई थी। संशोधित कीमतें अप्रैल, 2021 से लागू हो जाएंगी। ■

'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' सिर्फ 553 कार्य दिवसों में 50 लाख पर्यटकों को आकर्षित कर एक अत्यंत लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा!

@PMOIndia

'अमृत महोत्सव' के शुभारंभ पर हम सभी भारत में बनी वस्तुओं के उपयोग का लें प्रण: अमित शाह

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित 'अमृत महोत्सव' का शुभारंभ करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन किया। अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने 12 मार्च को कहा कि गांधी जी की 1930 की 'दांडी यात्रा' ने स्वाधीनता संग्राम को बल दिया था, तो आज मोदी जी के नेतृत्व में 2021 की यह पदयात्रा 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को ऊर्जा देगी।

श्री शाह ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प की पूर्ति गांधी जी के स्वदेशी अभियान व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'वोकल फॉर लोकल' में ही समाहित है। मोदी जी ने बार-बार कहा है कि आने वाला समय भारत का है, परन्तु यह तभी सम्भव है जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि स्वदेशी वस्तुएं विशेषकर खादी हमें अपनी संस्कृति, संस्कार व जड़ों से जुड़े रहने में अहम भूमिका निभाती हैं। मोदी जी द्वारा स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के शुभारंभ पर आइए हम सभी भारत में बनी वस्तुओं के उपयोग का प्रण लें और देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएं।

मोदी जी के नेतृत्व में 2021 की यह पदयात्रा 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को ऊर्जा देगी

श्री शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' आह्वान पर मैंने भी निकट के खादी भंडार से एक अंगवस्त्र और डायरी खरीदी। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि आप भी मोदी जी की इस अपील में सहभागी बनें व अपने आस-पास से खरीदी स्वदेशी वस्तु को 'वोकल फॉर लोकल' के साथ साझा करें। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

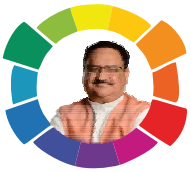

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

अहमदाबाद (गुजरात) स्थित साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में श्रीमद्भगवद्गीता की पांडुलिपि के साथ इसके श्लोकों पर 21 विद्वानों के भाष्य का विमोचन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

करीमगंज (असम) में एक विशाल जनसभा में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) में एक विशाल रैली को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 स्थिति पर मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh

@KamalSandesh

kamal.sandesh

KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20

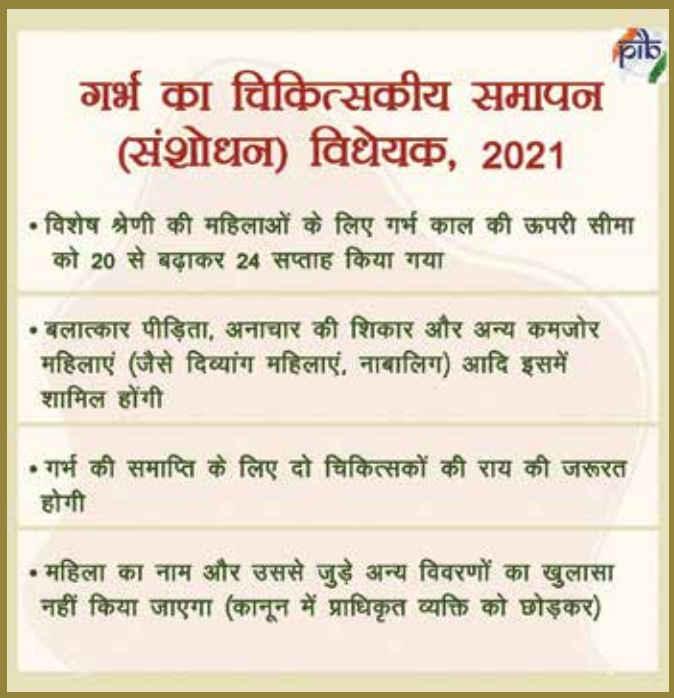

आवरण: अजय कुमार सिंह